माननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोएल, के. कन्नन और अलोक सिंह जे.आई.

भारत और संघ *OTHERS,* — *अपीलकर्ता बनाम*

KHUSHBASH *सिंह,* — *उत्तरदाता*

2009 का एलपीए नंबर 978

31 मार्च 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-सेना के पेंशन विनियम, 1961-पैरा 173-छुट्टी नियम-आर. आई. II-आकस्मिक/वार्षिक अवकाश के दौरान दुर्घटना में विकलांगता-छुट्टी-विकलांगता पेंशन के लिए दावा-इस आधार पर अस्वीकृति कि चोट सेना सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं है-इसके लिए चुनौती-आकस्मिक अवकाश या वार्षिक अवकाश पर रहते हुए सेना के एक कर्मी को ड्यूटी पर माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब अवकाश नियमों के नियम 11 के आधार पर, उसे ड्यूटी पर नहीं माना जा सकता था, यदि उसने वास्तव में उस वर्ष ड्यूटी का प्रदर्शन नहीं किया था-विकलांगता पेंशन के हकदार सैन्य कर्मियों को रखने वाले एकल न्यायाधीश का निर्णय-अपीलों को खारिज कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि आकस्मिक अवकाश या वार्षिक अवकाश पर रहते हुए सेना के किसी कार्मिक को ड्यूटी पर माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब छुट्टी नियमों के नियम1 के आधार पर, उसे ड्यूटी पर नहीं माना जा सकता है, यदि उसने वास्तव में उस वर्ष में ड्यूटी नहीं की थी। यदि वह ड्यूटी पर था और वह प्राकृतिक कारणों से विकलांगता से पीड़ित है, तो इस मुद्दे की जांच की जाएगी कि क्या यह सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार था या सैन्य सेवा द्वारा बढ़ाया गया था, सेना के कार्मिक के मामले को लेते हुए यह जांच की जाएगी कि क्या यह सेना सेवा का हस्तक्षेप था जो विकलांगता का कारण बना। शारीरिक चोट या सैन्य सेवा के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की जांच करने में चिकित्सा बोर्ड के निर्णय को प्रधानता प्राप्त होगी और न्यायालय आम तौर पर ऐसी वैज्ञानिक चिकित्सा राय द्वारा निर्देशित होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां विकलांगता का कारण बनने वाली चोट एक दुर्घटना के कारण होती है, जो कर्मियों के प्राकृतिक, रोगजनक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं होती है, सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या दुर्घटना का कारण बनने वाली गतिविधि या आचरण एक ऐसी गतिविधि का परिणाम था जो सैन्य सेवा

से भी दूर से जुड़ी हुई है। एक स्वतंत्र व्यवसाय या व्यवसाय या कॉलिंग की एक गतिविधि जो सैन्य सेवा के लिए असंगत होगी और ऐसी गतिविधि के दौरान होने वाली दुर्घटना को सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, कोई अन्य दुर्घटना, जो दूरस्थ रूप से जुड़ी हुई है और जो सैन्य सेवा के साथ असंगत नहीं है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति अस्पताल से लौट रहा है या सैन्य कर्मियों की सामान्य गतिविधियाँ कर रहा है, तब भी सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के रूप में लिया जाएगा।

.

(पैरा 18)

अनिल राथे, एडवोकेट और हेमेन अग्रवाल, एडवोकेट, के लिए *के अपीलकर्ता.*

भीम सेन सहगल, के लिए वकील *प्रतिवादी.*

क. कन्नन जे.

I.दांव पर लगा मुद्दा और पूर्ण पीठ को संदर्भित करने का कारण।.

(१) उपरोक्त दो मामले सेना के एक कर्मी द्वारा विकलांगता पेंशन के अधिकार के संदर्भ में एक ही मुद्दे को संबोधित करते हैं, जिसे छुट्टी के दौरान एक दुर्घटना में विकलांगता का सामना करना पड़ा। दोनों ही मामलों में, छुट्टी के दौरान दुर्घटनाओं के कारण विकलांगता उत्पन्न हुई। विकलांगता पेंशन की पात्रता सेना के पेंशन विनियमन के पैरा 173 पर आधारित है जो किसी विकलांगता के कारण उत्पन्न होने वाली विकलांगता पेंशन के लिए प्रावधान करता है, जो गैर-युद्ध दुर्घटना में सैन्य सेवा द्वारा जिम्मेदार या गंभीर है और जिसका आकलन 20% या उससे अधिक किया जाता है। अक्षमता के कारण संबंध की अभिव्यक्तियाँ जो एक गैर-युद्ध की स्थिति में सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार हैं, हमें यह जांचने के लिए ले जाएंगी कि सैन्य सेवा से संबंध रखने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों को लिया जा सकता है। मुद्दा फिर से यह होगा कि क्या कोई व्यक्ति, जो आकस्मिक छुट्टी या वार्षिक छुट्टी पर है, इस कारण संबंध का आकलन करने में किसी अलग मापदंड के अधीन होगा। एक पूर्ण पीठ का संदर्भ स्वयं एक खंड पीठ के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल) एक पैटी थे, ने देखा कि एक ओर जरनैल सिंह बनाम भारत संघ (1) में इस न्यायालय के खंड पीठ के निर्णय और इस न्यायालय के तीन अन्य निर्णयों के बीच विचारों का टकराव था। (2) पूजा और दूसरा बनाम भारत संघ और अन्य (3) और परगट सिंह बनाम भारत संघ और दूसरा C. W.P. में। नं. 1999 का 12434 22 सितंबर, 2006 को तय किया गया।.

(1) 1998 (1) एसएलआर 418
(2) 2008 (2) एस.सी.टी. 333
(3) 2009 (1) एस.सी.टी. 491

द्वितीय. मामलों को उनके तथ्यात्मक मैट्रिक्स और उनके मुकदमे में सेट करना यात्रा :

(2) दोनों मामलों में तथ्यात्मक स्थिति को सही ढंग से निर्धारित करना ताकि शामिल कानून की सराहना की जा सके, एलपीए सं। 2009 का 978, प्रत्यर्थी खुशबाश सिंह 8 फरवरी, 1974 को सेना में सिपाही के रूप में शामिल हुए और जब वे वर्ष 1988 में अपने गाँव गए थे तब आकस्मिक अवकाश पर थे। वह एक स्कूटर पर यात्रा करते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 60% विकलांगता के कारण उन्हें 1991 से छुट्टी दे दी गई। पेंशन का सेवा तत्व उन्हें दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा दावा की गई विकलांगता पेंशन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि वह स्वीकार्य नहीं थी। एलपीए नं. 2009 का 49, रिट याचिकाकर्ता ने 1979 से 1982 तक सेना की सेवा की थी, जब वह वर्ष 1992 में वार्षिक अवकाश पर था और जब वह माता चिंतपुरानी गया था। उन्हें चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस आधार पर विकलांगता पेंशन से इनकार कर दिया गया था कि चोट सेना सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं थी।.

(3) (3) LPAN0 में प्रत्यर्थी। 2009 के 978 ने विकलांगता पेंशन के लिए उनके दावे की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी और इसे मदन सिंह शेखावत बनाम भारत सरकार (4) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। सिपाही हयात मोहम्मद बनाम भारत संघ और अन्य (5). जब अपील डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो यह बताया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले में एक्स। सिपाही हयात मोहम्मद के मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने दिलबाग सिंह और अन्य (पूर्व। एनके.) बनाम भारत संघ और अन्य (6). पूर्ण पीठ के बाद के फैसले को यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम सुमनजीत सिंह (7) में उद्धृत किया गया था, जो L.P.A. में अपील का विषय था। 2009 का 49, जब मूल रूप से एक खंड पीठ ने भारत संघ द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई विकलांगता पेंशन का दावा नहीं किया जाएगा, जिसे वार्षिक अवकाश पर दुर्घटना में विकलांगता का सामना करना पड़ा था। यह निर्णय प्रत्यर्थी (सेना कर्मचारी) की ओर से पेश वकील की अनुपस्थिति में दिया गया था और समीक्षा के लिए एक आवेदन पर, निर्णय को दरकिनार कर दिया गया था और यह अन्य अपील के साथ योग्यता के आधार पर विचार के लिए भी आया था।.

(4) .

(5) AIR 1999 SC 3378
(6) 2008 (1) एस.सी.टी. 425
(7) 2008 (4) एस.सी.टी. 432
(8) 2009 (4) एस.सी.टी. 44

तृतीय. लिंचपिन पेंशन विनियम :

(४) इन दो अपीलों में उत्पन्न प्रश्न पर विचार करने के लिए, यह एनी के पेंशन विनियमन के पैरा 173 को पुन: पेश करने के लिए फलदायी होगा, 1961

> *"जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक एक विकलांगता होती है सेवा तत्व और विकलांगता तत्व प्रदान किया जा सकता है किसी व्यक्ति को, जिसे सेवा से बाहर कर दिया जाता है विकलांगता का खाता जो जिम्मेदार या उत्तेजित है गैर-युद्ध हताहत में सैन्य सेवा द्वारा और मूल्यांकन किया जाता है 20% या उससे अधिक पर."*

विनियमों के दो अन्य सेटों की भी जांच करनी होगी, जो "जिम्मेदार या बढ़े हुए" अभिव्यक्ति और "छुट्टी" से संबंधित प्रावधानों का संदर्भ देते हैं, क्योंकि हम आकस्मिक छुट्टी और वार्षिक छुट्टी के दौरान दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली विकलांगता के सवाल पर विचार कर रहे हैं। सेना अधिनियम, 1961 के पेंशन विनियमन के परिशिष्ट I को विनियम 48,173 और 185 के साथ पढ़ने का निर्देश दिया गया है* पेंशन विनियमों के नियम 48 में यह प्रावधान है कि अधिकारी, जो विकलांगता के कारण सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त होता है, जो ऐसी सेवा के कारण जिम्मेदार है या गंभीर है और सेवानिवृत्ति पर 20% या उससे अधिक का मूल्यांकन किया जाता है, उसे विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया जा सकता है। उक्त नियम में यह प्रावधान है कि यह प्रश्न कि क्या कोई विकलांगता सैन्य सेवा के कारण है या बढ़ी है, नियमों और परिशिष्ट I के तहत निर्धारित किया जाएगा। विनियमन 185 विकलांगता पेंशन के अनुदान की अवधि को संदर्भित करता है जब अमान्य विकलांगता सुधार करने में सक्षम है और इसलिए, यह थोड़ी अलग स्थिति को संबोधित करता है और हमें इसे यहां संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। परिशिष्ट I में 1982 के आकस्मिक पेंशन पुरस्कारों के लिए पेंशन विनियमन और पात्रता नियमों को लागू करने के लिए प्रासंगिक स्थितियों को रेखांकित किया गया है। नियम 1 से 4 उन व्यक्तियों के वर्गों के लिए नियमों की प्रयोज्यता से संबंधित है, जो निर्दिष्ट अवधि और नियम 5 के बीच रोजगार में थे, कुछ अनुमानों के साथ विकलांगता के मूल्यांकन को निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को कैसे स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति में माना जाएगा और नियम 6 प्रमाणन की प्रकृति को निर्धारित करता है जो आवश्यक होगा। नियम 8 महत्वपूर्ण है, जिसे पुनः प्रस्तुत किया गया है: यदि सैन्य सेवा में मृत्यु/अक्षमता के बीच कारण संबंध उपयुक्त

चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो विशेषता/उत्तेजना को स्वीकार किया जाएगा। नियम 9 प्रमाण की जिम्मेदारी के मुद्दे को निर्धारित करता है, जो फिर से महत्वपूर्ण है और इसलिए पुनः प्रस्तुत किया गया है::

'दावेदार को पात्रता की शर्तों को साबित करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा. वह किसी भी उचित संदेह का लाभ प्राप्त करेगा. यह लाभ होगा क्षेत्र/एफ्लोट सेवा मामलों में दावेदार को अधिक उदारता से दिया जाए." नियम 10 और 11 पोस्ट डिस्चार्ज दावों का उल्लेख करते हैं. नियम 10 स्थिति को संबोधित करता है एक पेनन की विकलांगता जो एक विशेष संख्या के बाद उत्पन्न होती है सेवा का निर्वहन, जिसे जिम्मेदार माना जा सकता है सर्विस. चूंकि हम विकलांगता के मामले की जांच कर रहे हैं दुर्घटना, हम उसी की जांच नहीं कर रहे हैं. नियम 11 एक विकलांगता के बारे में बोलता है उस समय के दौरान उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति जो विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहा है घर पर मर जाता है. हम फिर से मरने वाले व्यक्ति की स्थिति की जांच नहीं कर रहे हैं घर पर जब विकलांगता पेंशन का पहले से ही आकलन किया गया हो. नियम 12 परिभाषित करता है "कर्तव्य" और चूंकि पूर्ण बेंच के संदर्भ में एक व्याख्या है अट्रिबिलिटी या वृद्धि या सैन्य सेवा के लिए, यह होना आवश्यक है पुन: पेश किया गया :

"12. कर्तव्य.

सशस्त्र बलों के अनुशासनात्मक कोड के अधीन एक व्यक्ति है `कर्तव्य' पर: —

(a) आधिकारिक कार्य या कार्य विफलता करते समय जो उसके लिए लागू अनुशासनात्मक कोड के तहत एक अपराध का गठन करेगा.

(b) ड्यूटी के एक स्थान से दूसरी जगह जाते समय आंदोलन के बावजूद कर्तव्य.

(c) भर्ती में भागीदारी की अवधि के दौरान और सेवा द्वारा आयोजित या अनुमत अन्य इकाई गतिविधियाँ अधिकारियों और एक निर्धारित या संगठित मार्ग द्वारा एकल के शरीर में यात्रा की अवधि के दौरान.

ध्यान दें.

(ए) सशस्त्र बल के कार्मिक में भाग लेना: —

(i) स्थानीय/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट के रूप में सेवा दल के सदस्य, या

(ii) *पर्वतारोहण अभियान/ ग्लाइडिंग द्वारा आयोजित सेवा के अनुमोदन के साथ सेवा प्राधिकरण इन नियमों के उद्देश्य के लिए मुख्यालय को 'ON DUTY' माना जाएगा.*

(iii) नामित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले या निजी रूप से आयोजित पर्वतारोहण अभियानों में भाग लेने वाले या अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक शौक के रूप में ग्लाइडिंग में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को इन नियमों के उद्देश्य के लिए विधिवत नहीं माना जाएगा, भले ही उनके द्वारा सक्षम सेवा अधिकारियों की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई हो।.

नोट 2.

सशस्त्र बलों के कर्मियों ने प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति की हिमालयन पर्वतारोहण द्वारा संचालित पाठ्यक्रम संस्थान, दार्जिलिंग का इलाज अन्य अधिकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या अभ्यासों में भाग लेने वाले कर्मियों के साथ किया जाएगा के अनुदान के उद्देश्य के लिए रक्षा सेवा के लिए विकलांगता / पारिवारिक पेंशन खाते में व्यवहार्यता / मृत्यु पाठ्यक्रमों के दौरान निरंतर.

(d) अपने ड्यूटी स्टेशन से अपने लीव स्टेशन पर जाने वाले या अपने लीव स्टेशन से ड्यूटी पर लौटने वाले पुरुष, सार्वजनिक खर्चों पर यात्रा करने के हकदार हैं, यानी i.e. रेलवे वारंट पर, रियायती वाउचर पर, नकद टीए है (चाहे रेलवे वारंट/ नकद T.A. पूरी यात्रा के लिए या केवल एक हिस्से के लिए, सरकारी परिवहन में या जब यात्रा के लिए सड़क माइलेज का भुगतान/ भुगतान किया जाता है,,

(e) जब कोई अपने क्वार्टर से ड्यूटी के निर्दिष्ट स्थान तक यात्रा करता है और उचित मार्ग से लौटता है, पूर्व निर्धारित योजनाओं के हिस्से के रूप में, या निजी वाहन द्वारा जब कोई सेवा परिवहन का उपयोग करने के लिए योग्य होता है, लेकिन इसकी पेशकश नहीं की जाती है।.

a) (च) एक दुर्घटना जो तब होती है जब एक व्यक्ति सख्ती से 'ड्यूटी पर' नहीं होता है जैसा कि परिभाषित किया गया है, सेवा के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, बशर्ते कि इसमें जोखिम शामिल था जो निश्चित रूप से उसकी सेवा की प्रकृति, शर्तों, दायित्वों या घटनाओं द्वारा प्रकार या डिग्री में बढ़ाया गया था और यह कि यह भारत में आधुनिक परिस्थितियों में

मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम नहीं था। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित होने के कारण किसी अन्य भाग से मारा जाता है या घायल हो जाता है, तो उसे संबंधित समय पर 'ऑन ड्यूटी' माना जाएगा। यह लाभ सेना/नौसेना/वायु सेना अधिनियम में परिभाषित सक्रिय सेवा पर होने के मामले में ग्राहक को अधिक उदारता से दिया जाएगा।

कर्तव्य का संवैधानिक विस्तार कारण साबित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है दुर्घटना स्थितियों में कनेक्शन

(5) नियम 12 के मुद्दे पर विचार करने के लिए हमारे पास प्रासंगिकता है सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है क्योंकि हम सचमुच एक डीमिंग लागू कर रहे हैं प्रावधान. दोनों मामलों में, याचिकाकर्ता ड्यूटी पर थे और वे थे वास्तव में सैन्य अभियानों में नहीं लगे थे और न ही वे भीतर ही सीमित थे सैन्य गतिविधि के क्षेत्र. स्थितियों में से प्रत्येक, जो नियम 12 चिंतन करता है, मानता है कि एक व्यक्ति केवल अपने अंकन से कर्तव्य पर है रजिस्टर में उपस्थिति. उदाहरण के लिए, खेल टूर्नामेंट में भागीदारी सेवा दल के सदस्य के रूप में, पर्वतारोहण अभियान, से उनकी यात्रा अपने ड्यूटी स्टेशन को अपने अवकाश स्टेशन या जब उसकी दुर्घटना होती है सेना के कार्मिक के रूप में एक व्यक्ति की पहचान, जो सामान्य रूप से नहीं है मॉडेम स्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम. यह डीमिंग नियम 12 में निहित प्रावधान ने हमें एक सुराग दियायह एक निश्चित यथार्थवादी लगता है एक सेना कार्मिक जो विकलांगता प्राप्त करता है, उसे हमेशा दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होती है साबित करें कि वह ड्यूटी के अपने कॉल के दायरे में था. यदि कोई है नियम 12 के भीतर मौजूद परिचर परिस्थितियां आकर्षित होती हैं, आगे नहीं कारण कनेक्शन के बारे में प्रश्न पूछना होगा. ए नियम 12 के भीतर निर्दिष्ट परिस्थितियों के दौरान उत्पन्न होने वाली विकलांगता द्वारा विकलांगता को एक विकलांगता के रूप में लिया जा सकता है या इसके कारण बढ़ सकता है सैन्य सेवा.

V. वार्षिक या आकस्मिक अवकाश पर पेंशन को ड्यूटी पर रहते हुए अर्जित माना जाता है, जब तक कि कर्मचारी उस वर्ष के दौरान ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है।

(6) मुद्दा बस वहाँ समाप्त नहीं होता है. हम जांच करने की कोशिश कर रहेहैंक्या नियम 12 से परे, छुट्टी के दौरान किसी व्यक्ति की एक सामान्य गतिविधि

विकलांगता के परिणाम भी एक अभिव्यक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे सैन्य सेवा के लिए. चूंकि हम विकलांगता के मुद्दे की जांच कर रहे हैं

छुट्टी के दौरान, अवकाश नियमों से संबंधित संदर्भ भी प्रासंगिक हो जाता है. नियम 10 आकस्मिक अवकाश को संदर्भित करता है और नियम 11 वार्षिक अवकाश को संदर्भित करता है. यह है दोनों नियमों को पुन: पेश करने के लिए उपयुक्त :

आकस्मिक अवकाश

"10 नियम के रूप में दिए गए को छोड़कर ड्यूटी के रूप में गिना जाता है 11 (क)। —

इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के पूरक के लिए नहीं किया जा सकता है या अनुपस्थिति, नियम 72 के खंड (ए) में दिए गए को छोड़कर खेल आयोजनों में भाग लेने वाले कर्मियों के लिए और टूर्नामेंट.

एक वर्ष में देय कारण अवकाश केवल उसी वर्ष के भीतर लिया जा सकता है। यदि, तथापि, किसी व्यक्ति को अगले वर्ष तक विस्तारित वर्ष के अंत में आकस्मिक अवकाश दिया जाता है, तो बाद के वर्ष में आने वाली अवधि उस वर्ष की आकस्मिक अवकाश पात्रता के विरुद्ध डेबिट की जाएगी।"

वार्षिक अवकाश

"11 (ए) किसी भी वर्ष में वार्षिक अवकाश स्वीकार्य नहीं है जब तक कि कोई व्यक्ति नहीं वास्तव में उस वर्ष में कर्तव्य निभाया है. इसके प्रयोजनों के लिए नियम, आकस्मिक छुट्टी पर एक व्यक्ति को नहीं माना जाएगा वास्तव में इस तरह की छुट्टी के दौरान ड्यूटी की. खर्च की गई अवधि 'बीमार सूची रियायत' पर एक व्यक्ति द्वारा, हालांकि, कर्तव्य के वास्तविक प्रदर्शन के रूप में माना जाता है:

(b) वर्ष के लिए वार्षिक अवकाश, अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर, उस वर्ष के लिए अधिकृत वार्षिक अवकाश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगले कैलेंडर वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है

जिसमें विस्तारित अवकाश समाप्त हो जाता है, लेकिन आगे वार्षिक अवकाश तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति फिर से कर्तव्य का पालन नहीं करता है।.

(c) उसी वर्ष के भीतर किश्तों में वार्षिक अवकाश लिया जा सकता है.

(d) वार्षिक अवकाश वर्ष कैलेंडर वर्ष है, अर्थात। 1 जनवरी से 31 दिसंबर."

(7) जहाँ तक, एक स्पष्ट कथन है कि एक आकस्मिक छुट्टी को कर्तव्य के रूप में गिना जाएगा, इसे नियम 12 को एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के रूप में लिया जाना चाहिए। नियम I में विशेष रूप से कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश पर किसी व्यक्ति को उस अवकाश के दौरान ड्यूटी पर नहीं माना जाएगा जो किसी भी वर्ष में स्वीकार्य नहीं था, यदि व्यक्ति ने वास्तव में उस वर्ष में कर्तव्य का पालन नहीं किया था। वार्षिक अवकाश पर किसी व्यक्ति के कर्तव्य पर विचार करने का तरीका स्वयं संदेह में नहीं है, क्योंकि ऊपर बताए गए नियम 10 में निहित अपवाद केवल तभी है जब किसी व्यक्ति ने उस वर्ष कर्तव्य का पालन नहीं किया था।

छठी। दुर्घटनाओं और प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली विकलांगता-पत्र मामलों में चिकित्सा राय की प्रधानता.

(8) यह इस संदर्भ में है कि कई अन्य निर्णयों का संदर्भ, कारण संबंध की व्याख्या के संबंध में, जिसकी परिकल्पना विनियमन 173 में की गई है, प्रासंगिकता प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति सेवा में होता है तो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली विकलांगता के संदर्भ में चिकित्सा साक्ष्य पर अधिक निर्भरता संभव हो सकती है, ऐसे मामले में आवश्यक नहीं हो सकता है जहां हम दुर्घटना के कारण विकलांगता के कारणों की जांच कर रहे हैं। पूर्व में एक चिकित्सा साक्ष्य की विश्वसनीयता उस विशेष वैज्ञानिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो सकती है जो एक चिकित्सा पेशेवर के पास सैन्य सेवा के परिणामस्वरूप विकलांगता की विशेष प्रगति के प्राकृतिक कारणों पर नज़र रखने में हो सकता है या ऐसी सेवा से बढ़ जाता है। चिकित्सा साक्ष्य उन मामलों में भी प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं जहां हम दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मामलों या विकलांगता की जांच कर रहे हैं जहां विकलांगता का निकटतम कारण तलाशना दूर नहीं है। यह दुर्घटना ही है जिसके परिणामस्वरूप विकलांगता होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी दुर्घटना को भी सैन्य सेवा द्वारा जिम्मेदार या गंभीर बताया जा सकता है।.

(9) इसलिए, हम उन निर्णयों की गणना से दूर रहने का प्रयास करेंगे जहां विकलांगता प्राकृतिक कारणों से हुई थी और दुर्घटनाओं से उत्पन्न नहीं हुई थी और जहां सैन्य सेवा के विकलांगता के कारण संबंध के संबंध में चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है। निसन्देह ऐसी परिस्थितियों में, चिकित्सा रिपोर्ट स्वयं एक वैज्ञानिक चिकित्सा परीक्षा द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रधानता प्राप्त करेगी कि क्या विशेष विकलांगता सैन्य सेवा के कारण थी या सैन्य सेवा द्वारा बढ़ाई जा सकती थी, न्यायालय से बहुत कम हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी जैसा कि भारत संघ बनाम सुरेंद्र सिंह राठौर (8) में अभिनिर्धारित किया गया था उस मामले में, सेना कार्मिक मैकुलोपैथी (आरटी) आई से पीड़ित था, जिसके लिए उसे उपचार दिया गया था, लेकिन कोई सुधार नहीं पाया गया था।. उन्हें रिलीज मेडिकल बोर्ड को भेजा गया और बोर्ड ने मेडिकल श्रेणी "सीईई पेन एनेंट" में प्रतिवादी की रिहाई की सिफारिश की, जो श्रेणी "एवाईई" से कम थी। बोर्ड ने राय दी कि विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही बढ़ रही थी और बोर्ड की कार्यवाही को सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। नतीजतन, प्रत्यर्थी को भी सेवा से छुट्टी दे दी गई थी। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में हस्तक्षेप किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होनी

चाहिए थी। भारत संघ बनाम धीर सिंह चीन (9) फिर से एक ऐसा मामला था जिसमें चिकित्सा बोर्ड के विचार की प्रधानता देखी गई थी और विशेष विकलांगता के मामले को सैन्य सेवा द्वारा जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था या बढ़ाया गया था, जबकि संघ द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को दरकिनार करते हुए बरकरार रखा गया था। कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (पेंशन) बनाम एस. बालचंद्रन नायर (10) में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में रेडियो मशीन के कार्यालय में काम करने वाले एक सैन्य कर्मी को 'एंग्जाइटी न्यूरोसिस' विकसित पाया गया और लंबे समय तक इलाज के बाद सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य पाया गया। विकलांग पेंशन का दावा उनके द्वारा तब किया गया था जब मेडिकल बोर्ड ने राय दी थी कि वह एक संवैधानिक बीमारी से पीड़ित थे जिसका सेवा शर्तों से कोई संबंध नहीं था। मेडिकल बोर्ड, जो एक विशेषज्ञ निकाय था, की राय को उच्च न्यायालय ने तब दरकिनार कर दिया जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहने के लिए फिर से हस्तक्षेप किया कि ऐसे मामले में अनुच्छेद 226 के तहत विशेषज्ञ निकाय की राय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था और राय के साथ हस्तक्षेप की विशेषता बताई, जैसा कि आवश्यक नहीं था। उपरोक्त सभी मामलों में, यह देखा जा सकता है कि विशेष प्रतिशत से अधिक विकलांगता थी। विकलांगता फिर से तब उत्पन्न हुई जब व्यक्ति सेवा में था। एट्रिब्यूशन टेस्ट इनमें से प्रत्येक मामले में विफल रहा जहां विकलांगता के निकटवर्ती कारण का आकलन करने की आवश्यकता थी और पाया गया कि विकलांगता सेवा की स्थिति से जुड़ी नहीं थी। यदि मनोवैज्ञानिक कारक द्वारा प्रेरित कोई शारीरिक दोष या बीमारी मौजूद है, तो डॉक्टर का प्रमाणन और उसकी योग्यता की राय उच्चतम विश्वसनीयता प्राप्त करेगी।.

VB. सेना के कर्मियों के 'कर्तव्य' के दौरान विकलांगता की जांच इस संदर्भ में की जाएगी कि क्या दुर्घटना के लिए अग्रणी अधिनियम सैन्य कर्तव्य के साथ असंगत है.

(10) अवसरों के दौरान सेना के कार्मिक को होने वाली विकलांगता, जिसे नियम भी 'ऑन ड्यूटी' के रूप में निर्दिष्ट करते हैं, दूसरे प्रकार की स्थितियां होंगी, जिनकी हमें जांच करने की आवश्यकता है। यहाँ फिर से, उपरोक्त मामलों के पहले सेट की तरह, इस तथ्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि सेवा के दौरान या जब वह ड्यूटी पर थे तो चोट लगी थी। हम पहले ही परिशिष्ट I के खंड 12 में निर्दिष्ट "ऑन ड्यूटी" की परिभाषा के माध्यम से प्राप्त एक काल्पनिक कल्पना की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। वे सरल स्थितियाँ हैं जहाँ हालांकि वास्तव में ड्यूटी पर नहीं बल्कि एक कल्पना द्वारा, सेना के कार्मिक के साथ ड्यूटी पर व्यवहार किया जाएगा और ऐसे समय के दौरान उत्पन्न होने वाली विकलांगता होगी, उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने ड्यूटी स्टेशन से लीव स्टेशन तक पारगमन पर विकलांगता का सामना करता है जब वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो विकलांगता को केवल सेना की ड्यूटी के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इस स्थिति को

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मदन सिंह शेखावत बनाम भारत संघ मामले में संबोधित किया था (11). माननीय उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे की जांच कर रहा था जो विनियमन 48 के तहत निहित था, कर्तव्य पर रहते हुए चोटिल व्यक्ति के दृष्टिकोण से और इसे एक ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में पढ़कर, जिसे सार्वजनिक व्यय पर अपने छुट्टी स्टेशन पर जाने या अपने सेवा स्टेशन के लिए कर्तव्य पर लौटने पर कर्तव्य पर माना जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति, जो आकस्मिक अवकाश पर अपने खर्च पर अपने गृह स्टेशन जाता है और यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका हाथ काट दिया जाता है, हालांकि सार्वजनिक खर्च पर नहीं, उस व्यक्ति को विकलांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "सार्वजनिक व्यय" पद को इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि सेना अधिकारी को छुट्टी स्टेशन के लिए यात्रा करने के लिए अधिकृत किया गया था।

.

(११) यह मदन सिंह शेखावत के मामले (उपर्युक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जो शाब्दिक व्याख्या को त्यागने और आकस्मिक अवकाश के दौरान एक दुर्घटना के माध्यम से विकलांगता का सामना करने वाले व्यक्ति के तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता का परिचय देता है, जिसे एक कानूनी कल्पना के माध्यम से कर्तव्य पर माना जाएगा। अक्षमता का निकटतम कारण, इस मामले में, एक दुर्घटना थी। यहाँ, विकलांगता पेंशन प्रदान करते समय, एट्रिब्यूशन या उग्रता परीक्षण एक पीछे की सीट लेता है, हालांकि अभी भी एक प्रासंगिक परीक्षण है। पहला मुद्दा यह देखना है कि क्या किसी व्यक्ति, जो ड्यूटी पर है, को दुर्घटना में चोट लगी है, जिसे अभी भी केवल सेना सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाता है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण से दृष्टिकोण को उलटकर, अर्थात्, क्या सेना के कर्मियों ने कोई ऐसा कार्य किया था, जिसे करने की अनुमति सैन्य सेवा नहीं दे सकती थी। यदि यह किसी ऐसी गतिविधि के साथ असंगत था जो सामान्य रूप से सैन्य सेवा में होती है, तो इस तरह के आचरण से पीड़ित विकलांगता को चिकित्सा सेवा द्वारा प्रभावित या बाधित नहीं किया जा सकता था। यदि यह असंगत नहीं था, लेकिन एक दुर्घटना थी जब उसे अभी भी ड्यूटी पर माना जाता था, तो ऐसी विकलांगता से विकलांगता पेंशन का दावा संभव हो जाएगा।

.

(१२) उपरोक्त व्याख्या को इस संदर्भ में समझाया जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति, जो ड्यूटी के दौरान नशे में होने के कारण खुद को झगड़े में शामिल करता है। इसे निश्चित रूप से एक ऐसा कार्य नहीं कहा जा सकता जो एक सैन्य सेवा के अनुरूप हो। पुनः, ऐसी स्थिति हो सकती है कि वह किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न हो सकता है, जिसमें यदि वह ड्यूटी पर होता, तो वह शामिल नहीं हो सकता था, जैसे कि जब वह एक अलग व्यवसाय कर रहा होता या जब वह

किसी अन्य व्यवसाय में भाग ले रहा होता। एक और उदाहरण लेने के लिए, मान लीजिए कि वह कृषि में भाग ले रहा है। उपर्युक्त प्रकार की गतिविधियों में से प्रत्येक में सेना कर्मी एक गतिविधि कर रहा है, जो रक्षा सेवा में एक व्यक्ति के रूप में वह नहीं कर सकता था यदि वह ड्यूटी के स्थान पर वापस रहता, जैसे कि सेना शिविर। यदि अंतर को कुछ निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है, जिन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं विचार किया है। सचिव, रक्षा मंत्रालय और अन्य बनाम अजीत सिंह (12) में प्रतिवादी रक्षा कर्मी को बिजली के झटके के कारण 20% विकलांगता का सामना करना पड़ा, जब वह आकस्मिक छुट्टी पर था और एक ट्यूबवेल के पास अपने घर में काम कर रहा था। इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने 10 साल की सेवा भी पूरी नहीं की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि वह विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं थे। इस मामले में यह देखा जा सकता है कि वह आकस्मिक अवकाश पर था और इसलिए, वह कर्तव्य पर माने जाने का हकदार था। उन्हें बिजली के झटके की दुर्घटना हुई थी, लेकिन वह दुर्घटना तब हुई जब वे सैन्य सेवा में एक व्यक्ति के कार्य से असंगत कार्य में भाग ले रहे थे। हालांकि मामले में दिए गए तथ्य पूर्ण नहीं हैं, हम यह मानने का साहस करते हैं कि बोरवेल में झटका घरेलू गतिविधि के लिए नहीं था। यह एक कृषि अभियान था, जो सैन्य सेवा के साथ असंगत था। हमारा मानना है कि इस तरह का अंतर मौजूद है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं लांस दफादार, जोगिंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (13) में एक अन्य मामले में एक मामले में आयोजित किया है, जिसमें याचिकाकर्ता, लांस दफादार के रूप में सेना में सेवा करते समय उस समय दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था जब वह आकस्मिक अवकाश पर था। यह दुर्घटना ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुई जब वह ट्रेन से नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका दाहिना पैर चलती ट्रेन के पहियों के नीचे आ गया और इस तरह वे घुटने के नीचे कुचल गए। इस मामले में, सेना के कर्मियों को कम से कम यह दिखाने का फायदा था कि वह आकस्मिक छुट्टी पर जा रहे थे और इसलिए, ड्यूटी पर थे। पुनः, परिशिष्ट I, खंड 12 ने स्वयं उसके लिए यह उपबंध किया कि उसके ड्यूटी स्टेशन से उसके लीव स्टेशन तक की यात्रा के दौरान लगी चोट को सेना के कर्तव्य के कारण माना जाएगा। स्थिति वैसी ही थी जैसी हमने पहले ही मदन सिंह शेखावत के मामले में देखी है।

.

(13) अक्षमता की ओर ले जाने वाली गैर-दुर्घटना चोट हमेशा अलग होती है, क्योंकि इस मुद्दे पर चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण से विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसी अक्षमता सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न हुई है या नहीं, जैसा कि एस बालचंद्रन नायर, सुरिंदर सिंह राठौर और धीर सिंह चीन में जांच की गई है। (supra). संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम बालजीत सिंह (14k) में एक निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसके बाद सचिव, रक्षा मंत्रालय और अन्य

बनाम A.V. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया। एल. आर. और अन्य के माध्यम से दामोदरन (मृत) (15)..

(14) दुर्घटना से उत्पन्न विकलांगता के मामलों में ध्यान का केंद्र हमें चिकित्सा राय से केवल यह देखने के लिए दूर करता है कि क्या गतिविधि निषिद्ध है या सैन्य सेवा के लिए असंगत है। यह केवल देखने की जरूरत है कि दुर्घटना तब हुई होगी जब एक एमी कार्मिक सैन्य सेवा में था। अस्पताल से घर की ओर मोटर-साइकिल या साइकिल से या यहां तक कि एक पैदल यात्री के रूप में यात्रा करना इस तरह की गतिविधि करने वाले सेना के कार्मिक के आचरण के अनुरूप हो सकता है, भले ही वह ड्यूटी स्टेशन पर रहा हो।. यदि हम ऐसी अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं तो यह तथ्य कि कोई व्यक्ति कार्यस्थल से कारण छुट्टी या वार्षिक छुट्टी पर था, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि यह गतिविधि एक असैन्य गतिविधि नहीं लग सकती। हम पहले ही अवकाश नियम 10 और 1.1 में आकस्मिक अवकाश और वार्षिक अवकाश के बारे में देख चुके हैं, दोनों स्थितियों को केवल ड्यूटी पर ही लेना होगा। यदि केवल आकस्मिक छुट्टी या वार्षिक छुट्टी ऐसे समय में जारी रही है, जब उस वर्ष सेना के कर्मी ड्यूटी पर बिल्कुल नहीं थे, तो ऐसी छुट्टी को ड्यूटी पर नहीं माना जा सकता था। कोई अन्य छुट्टी कर्तव्य पर व्यक्ति के चरित्र को छीन नहीं सकती थी।. यदि, इसलिए, साइकिल या मोटर-साइकिल की सवारी करने वाले व्यक्ति द्वारा एक दुर्घटना होती है जब वह एक ऐसा कार्य कर रहा था जो एक सैन्य कार्मिक के कार्य के साथ असंगत नहीं था, तो इस तरह के कार्य से उत्पन्न होने वाली विकलांगता हमेशा केवल एक विकलांगता होगी जो सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार होगी। आखिरकार, हम गैर-युद्ध की स्थिति में उत्पन्न होने वाली विकलांगता की स्थिति की जांच कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को युद्ध के मोर्चे पर गोली लग जाती है और एक विकलांगता होती है जो पूरी तरह से एक अलग स्थिति है और रेस इप्सा लोकिटुर के सिद्धांत को आसानी से लागू किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि ऐसी चोट जो इस तरह के ऑपरेशन में विकलांगता का कारण बनती है, उसे हमेशा सेना की सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। फोरेंसिक अभ्यास केवल तभी आवश्यक हो जाता है जब हम इस बात की जांच करते हैं कि कैसे एक गैर-युद्ध की स्थिति में भी, विकलांगता पेंशन को अभी भी सैन्य सेवा के लिए स्रोत के रूप में प्राप्त किया जा सकता है या इसके कारण बढ़ सकता है। यदि हम उपरोक्त तर्क को अपनाएँ, तो यह देखा जा सकता है कि इस माननीय न्यायालय की खंड पीठ का पूजा और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (16) में निर्णय पूरी तरह से उचित था जब यह एक सैन्य कर्मी के मामले की जांच कर रहा था, जो वार्षिक अवकाश पर रहते हुए दुर्घटना का शिकार हो गया था। अदालत ने पाया

कि दुर्घटना उसके नियंत्रण से बाहर थी और आगे यह अभिनिर्धारित किया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यह केवल इसलिए कि वह छुट्टी पर था, उसे विकलांगता पेंशन देने के लिए अयोग्य घोषित कर देगा। डिवीजन बेंच ने एक्स में पहले के एक फैसले पर भरोसा किया। नायक किशन सिंह बनाम भारत संघ (17) जहां तथ्य समान थे, सिवाय इसके कि आगे के मामले में न्यायालय उस चोट से निपट रहा था जब सेना कर्मी आकस्मिक अवकाश पर थे। बाद के निर्णय ने मदन सिंह शेखावत के मामले में एक निर्णय का उल्लेख किया, जो एक दुर्घटना से पीड़ित एक सैन्यकर्मी की थोड़ी अलग स्थिति से संबंधित था, जब वह पारगमन पर था और इसमें पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया गया था। सिपाही हयात मोहम्मद बनाम भारत संघ और अन्य (18). संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह इंगित करेंगे कि पूर्व। सिपाही हयात मोहम्मद बनाम भारत संघ और अन्य को उसी उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा अलग कर दिया गया था।

(15) दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एक तर्क को अपनाया, जब सैन्य सेवा से विकलांगता के कारण संबंध को देखने के लिए अपनी खोज में, मदन सिंह शेखावत में तर्क को कुंद करने का फैसला किया, जैसा कि वकील की रियायत के माध्यम से प्राप्त किया गया था; इसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति आकस्मिक छुट्टी या वार्षिक छुट्टी पर था और इसने दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली विकलांगता और सैन्य सेवा के साथ असंगत कार्य करने के बीच के अंतर पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसने पाया कि आकस्मिक अवकाश के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति के मुद्दे पर इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए कि आकस्मिक अवकाश से संबंधित नियमों का उपचार केवल इस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए कि अवकाश के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी अन्य विचार की जांच के लिए नहीं कि क्या विकलांगता एक दुर्घटना है जिसे सैन्य कर्तव्य के कारण कहा जा सकता है या नहीं। हम दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में सम्मानपूर्वक भिन्न हैं, क्योंकि हमारे अनुसार, आकस्मिक अवकाश या वार्षिक अवकाश पर कोई व्यक्ति सैन्य ड्यूटी पर नहीं रहता है और दुर्घटना में उसे होने वाली चोट की जांच केवल इस संदर्भ से की जा सकती है कि क्या यह सैन्य सेवा में किसी व्यक्ति के साथ असंगत था या नहीं। विलियम्स बनाम पेंशन मंत्री (19) में पेंशन अपील ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1943 के तहत प्रावधानों से निपटने वाले किग्स बेंच डिवीजन में कमोबेश एक समान स्थिति पर, यह सवाल उठाते हुए कि क्या यह सैन्य सेवा के लिए 'जिम्मेदार' था, चोट से उत्पन्न विकलांगता पेंशन के अधिकार के मुद्दे पर विचार किया गया। उस मामले में भी, वास्तव में छुट्टी पर रहते हुए एक सैनिक को चोट लगी थी, परिस्थितियों में सेवा की मजबूरियों की

कोई भूमिका नहीं थी। उनकी दुर्घटना मोटर-साइकिल या साइकिल चलाते समय नहीं हुई थी, बल्कि जब वे एक राइफल को धूल से पोंछ रहे थे और पोंछ रहे थे, जब उन्होंने अपने बाएं पैर पर बैरल रखते हुए उसके बट को ऊपर की ओर पकड़ लिया था। यह सबूत के रूप में सामने लाया गया था कि वह यह न देखने में लापरवाही कर रहा था कि राइफल भरी हुई थी या नहीं। लेकिन यह एक गंभीर चोट थी और इसके कारण उन्हें छुट्टी दे दी गई। जब पेंशन का दावा किया गया था, तो जे. डेनिंग ने फैसला सुनाया था:: —

> "पहला सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या कारण के रूप में, चोट युद्ध सेवा के कारण थी। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या यह युद्ध सेवा के कारण भी था, यह अपीलार्थी की गंभीर लापरवाही या कदाचार के कारण था। पहले बिंदु पर, न्यायाधिकरण ने माना कि चोट युद्ध सेवा के कारण नहीं थी। ऐसा करने में, उन्होंने कमांड पेपर नं. 6459, जुलाई, 1943 में प्रकाशित, जिसमें यह कहा गया था कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में छुट्टी पर है, तब लगी चोट, सेवा की कोई भूमिका नहीं निभाने की मजबूरियों को उचित रूप से सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, उस कथन का कोई कानूनी बल नहीं है इन मामलों का निर्णय न्यायाधिकरणों द्वारा और इस न्यायालय द्वारा शाही वारंट के अनुसार किया जाना है, न कि उस आदेश पत्र के संदर्भ में। "सेवा की मजबूरी" शब्द शाही वारंट में नहीं आते हैं और किसी भी अर्थ में इन मामलों के लिए एक मार्गदर्शक नहीं हैं।
>
> यह दुर्घटना उस समय हुई जब वह व्यक्ति छुट्टी पर था। इसका श्रेय स्पष्ट रूप से युद्ध सेवा को दिया जाता था। यह हो सकता है कि उन्हें केसडन में इस समय अपनी राइफल को साफ करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, लेकिन यह उनकी युद्ध सेवा की एक घटना थी। यह हो सकता है कि वह लापरवाही कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुर्घटना युद्ध सेवा के कारण नहीं हुई थी। पहले बिंदु पर न्यायाधिकरण का निर्णय गलत था।"
>
> ."

(16) यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायालय इस स्थिति की जांच कर रहा था कि कैसे वह कार्य करने के लिए मजबूर नहीं था, जो वह इस समय कर रहा था। यह एक दुर्घटना थी; वह छुट्टी पर था और वह लापरवाही कर रहा था। अदालत ने फिर भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि दुर्घटना सेवा के कारण नहीं हुई थी। हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, फोर्थ एडिशन, रीइश्यू 2 (2)

2003 एडिशन में, पैरा 278 में, 'एट्रिब्यूटेबल टू सर्विस' अभिव्यक्ति का अर्थ इस प्रकार लाया गया है :

> उन्होंने कहा, "इस मुद्दे पर कि क्या चोट सर्विस के कारण लगी है, दो सवालों के जवाब दिए जाने चाहिएः पहला, चोट कब लगी? ; दूसरा, इसकी घटना के कारण क्या थे? यदि यह सेवा से पहले मौजूद था, तो इसे सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन इससे यह बढ़ सकता है। यदि यह सेवा के दौरान हुआ था और यदि सेवा इसकी घटना के कारणों में से एक थी तो यह सेवा के लिए जिम्मेदार है; लेकिन यदि सेवा इसकी घटना का कारण नहीं थी, तो इसे सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, हालांकि यह सेवा से बढ़ सकता है। चोट के लिए सेवा को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, सेवा चोट का कारण होना चाहिए, जो केवल उन परिस्थितियों का एक हिस्सा होने से अलग है या जिन पर कारण संचालित होता है। हालाँकि, यदि सेवा और सेवा के दौरान चोट नहीं लगती है, तो इसके कारणों में से एक है, चोट सेवा के लिए जिम्मेदार है, इसके बावजूद कि अन्य कारण भी मौजूद हैं, चोट पैदा करने के लिए सेवा के साथ सहयोग करना।"

उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि यदि सेवा के दौरान कोई विकलांगता उत्पन्न होती है और यदि सेवा इसकी घटना के कारणों में से एक थी, तो विशेषता के मुद्दे को समझना बहुत आसान हो जाता है। यह आम तौर पर एक ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां चोट सेवा के दौरान या बाहर होती है, श्रमिक मुआवजा अधिनियम से निपटने वाले औद्योगिक न्यायशास्त्र में हम जिन अभिव्यक्तियों से परिचित हैं, रोजगार के दौरान और बाहर हुई चोट वास्तव में स्थिति का जवाब नहीं देती है, जिसकी हम अब जांच कर रहे हैं। इस प्रकार एक कार्य, जो पूरी तरह से व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षेत्र के भीतर है, सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं है, जैसे कि, आत्महत्या स्वयं एक ऐसा कार्य है, जिसे सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आत्महत्या एक मध्यवर्ती और बाहरी घटना है जो मृत्यु का इतना शक्तिशाली कारण बनती है कि अन्य परिस्थितियाँ बिल्कुल भी कारण नहीं होती हैं, बल्कि उन परिस्थितियों का केवल एक हिस्सा होती हैं जिन पर कारण संचालित होता है (एक्सवाई बनाम पेंशन मंत्री। (20). हम उन स्थितियों की जांच नहीं कर रहे हैं जहां सेवा की मजबूरियों के कारण किसी व्यक्ति की स्थिति बिगड़ जाती है जिससे वह विकलांग हो जाता है। हम उन स्थितियों की भी जांच नहीं कर रहे हैं जहां किसी विशेष बीमारी का पूर्व-निपटान, जो सैन्य सेवा के दौरान बढ़ जाता है

और जिसके परिणामस्वरूप कुछ विकलांगता हो जाती है। एक बीमारी के लिए पूर्व-निपटान स्वयं एक बीमारी नहीं है, क्योंकि यह हमेशा माना गया है कि सशस्त्र बलों को एक आदमी को लेना चाहिए क्योंकि वे उसे बेकार पाते हैं, यह दिखाया गया है कि सेवा की शर्तों ने बीमारी के उत्पादन में कोई भूमिका नहीं निभाई, पेंशन प्रदान की जानी चाहिए (ब्राउन बनाम पेंशन मंत्रालय (21) हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड पैरा 278 में उद्धृत) हमने कई उदाहरण दिए हैं कि सैन्य सेवा के लिए क्या जिम्मेदार होगा और क्या नहीं होगा, केवल इसके सभी विविध पहलुओं में अभिव्यक्ति के अर्थ का विश्लेषण करें।.

आठवीं. संदर्भ को जगह देने वाले निर्णयों की जांच

(१ () अब इस बात का जायजा लेने का समय आ गया है कि इस संदर्भ को जन्म देने वाले अलग-अलग विचारों को कैसे हल किया जा सकता है। जरनैल सिंह बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि सेना अधिनियम के प्रावधानों के अधीन एक व्यक्ति, जब वह आकस्मिक अवकाश पर जाता है, तब भी उसे ड्यूटी पर माना जाएगा और वह कानून के अनुसार वहां से प्राप्त होने वाले लाभों का हकदार होगा। यदि सैन्य सेवा द्वारा अक्षमता की विशेषता और वृद्धि के लिए कोई दूरस्थ संबंध था, भले ही बल के सदस्य की ओर से लापरवाही या कदाचार का कोई तत्व हो, तो यह स्वयं सदस्य के इस तरह के दावे को उठाने के अधिकार को हतोत्साहित नहीं करेगा। हालांकि, डिवीजन बेंच ने कहा कि आकस्मिक अवकाश के दौरान खेतों में काम करना या खुद को व्यवसाय की कृषि गतिविधि में व्यस्त रखना सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार कार्य नहीं होगा। यह हमारे अपने तर्क के अनुरूप है कि यदि कोई कार्य सैन्य कर्तव्य से भी दूर से जुड़ा नहीं है, जैसे कि खेतों में काम करने वाला व्यक्ति <u>और आकस्मिक छुट्टी के दौरान भी व्यवसाय की कृषि गतिविधि में खुद को</u> शामिल करता है, तो उसे सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार कार्य नहीं माना जाएगा। यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता को गेहूं के थ्रेशर का संचालन करते समय चोट लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका दाहिना हाथ काट दिया गया था, पीठ ने तर्क दिया कि सेना सेवा के खतरों को गैरकानूनी और पूरी तरह से असंबद्ध गतिविधियों की सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब वह छुट्टी पर थे। पीठ ने यह भेद किया और हमारा विचार सही है कि बल का सदस्य विकलांगता पेंशन का दावा कर सकता है यदि उसे आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए चोट लगने से विकलांगता का सामना करना पड़ा, भले ही वह उसकी ओर से किसी लापरवाही या कदाचार से उत्पन्न हुआ हो, जहां तक कि इसका बल की प्रकृति से कोई संबंध या संबंध था। यहां तक कि सेवा के लिए दूरस्थ विशेषता और बल के सदस्य के रूप में व्यवहार और जीवन के अपेक्षित मानक नियम 173 के तहत दावा करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त प्रतीत होते हैं। बल के सदस्य की ओर से चूक और कमीशन के कार्य को विवेक, तर्कसंगतता और व्यवहार के अपेक्षित मानकों की कसौटी को पूरा करना चाहिए। उस मामले में

विकलांगता पेंशन के दावे को केवल इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि सेना सेवा से कारण संबंध की कमी थी। मुद्दा यह नहीं था कि उन्हें अभी भी ड्यूटी पर माना जाता था; यह भी नहीं था कि सेना के जवानों की ओर से कोई लापरवाही की गई थी या नहीं। दूसरी ओर, मुद्दा यह था कि क्या विशेष प्रकार की गतिविधि का सशस्त्र सेवा पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। पीठ ने पाया कि ऐसा नहीं था। गुरजित सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (ऊपर) जैसा कि हमने पहले ही जांच की है, उस समय दुर्घटना का मामला है जब सेना के जवान छुट्टी पर आए थे। अदालत ने विकलांगता पेंशन के दावे को बरकरार रखा था। यह निर्णय, हमने जो तर्क अपनाया है, वह जरनैल सिंह के मामले (ऊपर) पूजा और दूसरे बनाम भारत संघ और अन्य (ऊपर) में जो निर्णय लिया गया है, उसके अनुरूप नहीं है, जैसा कि गुरजीत सिंह के मामले में हुआ था और इसलिए, इसे जरनैल सिंह के मामले में तर्क की रेखा के साथ असंगत भी नहीं कहा जा सकता है। परगट सिंह के मामले में एक तर्क अपनाया गया था, जिस पर हमें अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निर्णय को ही वापस ले लिया गया था और हमने एक तर्क दिया है कि विकलांगता पेंशन के दावे को खारिज करने वाले उक्त फैसले में अपनाए गए तर्क को इस अदालत के समक्ष संबोधित किया गया था क्योंकि संघ की ओर से पेश वकील की दलीलें स्वीकार नहीं की जा सकती थीं।

नौवीं। वर्तमान स्वभाव

(18) हमने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और इस माननीय न्यायालय की खंड पीठ के निर्णयों द्वारा बताए गए नियमों के संदर्भ में पूरी विधि का वर्णन करने का प्रयास किया है। हम संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए देते हैं कि एक ओर जरनैल सिंह के निर्णयों और दूसरी ओर गुरजित सिंह और पूजा के निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है और दूसरी ओर आकस्मिक अवकाश या वार्षिक अवकाश पर सेना के कार्मिक को ड्यूटी पर माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब छुट्टी नियमों के नियम I के आधार पर, उसे ड्यूटी पर नहीं माना जा सकता था, अगर उसने वास्तव में उस वर्ष में ड्यूटी की थी। यदि वह ड्यूटी पर था और वह प्राकृतिक कारणों से विकलांगता से पीड़ित है, तो इस मुद्दे की जांच की जाएगी कि क्या यह सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार था या सैन्य सेवा द्वारा बढ़ाया गया था, सेना के कार्मिक के मामले को लेते हुए यह जांच की जाएगी कि क्या यह सेना सेवा का हस्तक्षेप था जो विकलांगता का कारण बना। -1 शारीरिक चोट या सैन्य सेवा के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की जांच करने में चिकित्सा बोर्ड के निर्णय को प्रधानता प्राप्त होगी और न्यायालय आम तौर पर ऐसी वैज्ञानिक चिकित्सा राय द्वारा निर्देशित होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां विकलांगता का कारण बनने वाली चोट एक दुर्घटना के कारण होती है, जो कर्मियों के प्राकृतिक, रोगजनक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं होती है, सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या दुर्घटना का कारण बनने वाली गतिविधि या आचरण एक ऐसी गतिविधि का परिणाम था जो सैन्य सेवा से भी दूर से जुड़ी हुई है। एक स्वतंत्र व्यवसाय या व्यवसाय या कॉलिंग की एक गतिविधि जो सैन्य सेवा के लिए असंगत होगी और ऐसी गतिविधि के दौरान होने वाली दुर्घटना को सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, कोई अन्य दुर्घटना, जो दूरस्थ रूप से जुड़ी हुई है और जो सैन्य सेवा के साथ असंगत नहीं है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति अस्पताल से लौट रहा है या सैन्य कर्मियों की सामान्य गतिविधियाँ कर रहा है, तब भी सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के रूप में लिया जाएगा।.

R.N.R.

(19) उपरोक्त तर्क पर, एकल न्यायाधीश का निर्णय खुशबाश सिंह एल. पी. ए. सं. 2009 के 978 की पुष्टि की गई है और एल. पी. ए. को खारिज कर दिया गया है। उसी तर्क के आधार पर, वार्षिक अवकाश के दौरान घायल हुए सेना कार्मिक द्वारा दायर रिट याचिका भी विकलांगता पेंशन का हकदार होगा और परिणामस्वरूप, एकल न्यायाधीश का निर्णय सही और पुष्ट है और संघ द्वारा एल. पी. ए. सं. 2009 का 49 भी खारिज कर दिया गया है।.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रेवाडी **(हरियाणा)**